मॉनसून सत्र के पहले दिन मोदी ने दिखाई कूटनीति

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी सदस्यों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी सदस्यों का अभिवादन किया। कार्यवाही शुरू होने से पांच मिनट पहले सदन में पहुंचे मोदी विपक्षी सदस्यों की तरफ बढ़े और पहली कतार में बैठे विपक्षी नेताओं का अभिवादन किया। पहली कतार में सोनिया गांधी के अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी.देवगौड़ा, समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मुलायम सिंह यादव, सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा उपाध्यक्ष एम.थंबीदुरई बैठे थे। मोदी ने देवगौड़ा, यादव, खड़गे तथा थंबीदुरई से हाथ मिलाया, जबकि सोनिया का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने खड़गे तथा यादव से संक्षिप्त बातचीत भी की। दूसरी कतार में बैठे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उन्होंने अभिवादन किया। सदन में दाखिल होने के तुरंत बाद मादा ने हाथ जाड़कर सदस्यों को प्रणाम किया। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) सदस्य रामचंद्र पासवान ने आदरस्वरूप मोदी के पांव छुए। मोदी के सदन में दाखिल होते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गए और प्रधानमंत्री के बैठने के बाद ही वे अपनी सीटों पर बैठे। इससे पहले दिन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने सभी पार्टियों से देशहित में काम करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि तीन सप्ताह से लंबे मॉनसून सत्र के दौरान सांसद देश हित में गुणवत्तापूर्ण चर्चा में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने आए मोदी ने कहा कि यह मॉनसून सत्र कई तरह से बेहद खास है, क्योंकि देश अपने नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। मोदी ने कहा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने उस अच्छाई को दर्शाया है, जिसे देशहित में सभी दलों के साथ मिलकर काम कर प्राप्त किया जा सका। जीएसटी की भावना हमारी मजबूती के बढ़ने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि जीएसटी के प्रति जो भावना थी, वह सत्र में बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह मॉनसून उम्मीदों का सूत्रपात करता है, 'यह सत्र भी वही उम्मीद लाता है।

कुर्सी संभालते ही कोविंद को करना होगा ये बड़ा फैसला!

क्या है मामला?

दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जिसको प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की। याचिकाकर्त्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का मामला लाभ के पद के दायरे में आता है और केजरीवाल सरकार ने इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर तमाम सरकारी सुविधाएं दी हैं। लिहाजा इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

नई दिल्ली,(आरएनएस)। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए आज हो रहे चुनाव का नतीजा 20 जुलाई को आएगा और 25 जुलाई तक देश के नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करते ही रामनाथ कोविंद के सामने अपने कार्यकाल का पहला बड़ा फैसला लेने की चुनौती होगी। ये फैसला आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का हो सकता है। चुनाव आयोग इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुका है और इस पर किसी भी समय आयोग का फैसला आ सकता है। ये फैसला आयोग राष्ट्रपति के पास भेजेगा और बतौर राष्ट्रपति कोविंद को आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर पहला बड़ा फैसला करना होगा। ये मामला मौजूदा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास पहुंचा था जिन्होंने इस मामले में आयोग से प्रेसीडेंशियल रेफरेंस मांगा था। आयोग पिछले 2 साल से इस मामले की सुनवाई कर रहा था और ये सुनवाई अब पूरी हो चुकी है।

क्या होगी प्रक्रिया?

चुनाव आयोग ने एक अर्द्धनायक बॉडी की तरह पूरे मामले की जांच की है और इस मामले में याचिका कर्त्ता प्रशांत पटेल और आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद यदि आयोग का फैसला आप के 21 विधायकों के खिलाफ जाता है तो उन्हें इस मामले में अदालत में चुनौती देना का पूरा अधिकार है। ये चुनौती तभी संभव हो सकेगी यदि राष्ट्रपति ने इस पर तुरंत फैसला न लिया। यदि राष्ट्रपति ने मामले में फैसला ले लिया तो मामले को अदालत की शरण में ले जाने का विकल्प खत्म हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

नहीं काम आई केजरीवाल की चाल

मामले के चुनाव आयोग में पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एक बिल पारित करके सीपीएस के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया था। आयोग ने इस मामले में याचिकाकर्त्ता की दलील की स्वीकार कर लिया था। इस बीच मामले में समानांतर कार्रवाई उच्चन्यायालय में भी चल रही थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दिल्ली के 21 संसदीय सचिवों की न्युक्ति को अवैध ठहरा दिया। जिसके चलते इन 21 विधायकों को संसदीय सचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

सरकारी बैंकों की संख्या घटा सकती है सरकार

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। केन्द्र सरकार पब्लिक सैक्टर बैंक की संख्या घटाकर 12 तक सीमित करने पर विचार कर रही है। सरकार इससे जुड़े एक एजैंडे पर काम कर रही है। इस एजैंडे के मुताबिक सरकार पब्लिक सैक्टर बैंक की संख्या घटाने के साथ ही 3-4 ग्लोबल लैवल के बैंक तैयार करने की योजना बना रही है।

ग्लोबल लैवल के बनेंगे 3 से 4 बैंक : एक अधिकारी ने बताया कि 21 पब्लिक सैक्टर बैंकों को मध्य अवधि में 10 से 12 में समेट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि थ्री-टायर स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 से 4 ऐसे बैंक बनाए जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक जितने बड़े होंगे। उस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि क्षेत्र संबंधी बैंक जैसे कि पंजाब और सिंध बैंक व आंध्रा बैंक स्वतंत्र बैंक के तौर पर काम करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ मिड-लैंडर्स भी अपने ऑप्रेशन चलाते रहेंगे।

सरकार कर रही तेजी से काम : पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर तेजी से काम कर रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया। एस.बी.आई. मर्जर से उत्साहित वित्त मंत्रालय ऐसा ही दूसरा प्रोपोजल क्लीयर करने पर विचार कर रहा है। हालांकि यह तब ही होने की उम्मीद है जब बैड लोन की स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के मुताबिक व्यवस्था में कुछ बड़े बैंक, कुछ छोटे और कुछ स्थानीय बैंक रहेंगे। उन्होंने कहा था कि सिस्टम में वैरायटी की जरूरत है।

कई बैंक बढ़ सकते हैं मर्जर की ओर

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि एक संभावना यह भी है कि पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.), बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया अधिग्रहण के लिए संभावित प्लेयर की खोज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ये बैंक रीजनल संतुलन, भौगोलिक पहुंच और वित्तीय दबाव व आसानी से मानव संसाधन तक पहुंच भी देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर बैंक को मजबूत बैंकों के साथ मर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

ट्राइब्यूनल ने रद्द किया 15 बैंकों पर जुर्माने का आदेश

0- मनी लॉन्ड्रिंग मामला

नई दिल्ली,(आरएनएस)। ट्राइब्यूनल ने उन 15 बैंकों पर जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है जिन पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप लगा था। इन बैंकों पर जुर्माना फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से लगाया गया था।

जुर्माने को किया खारिज जानकारी के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत काम करने वाले अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 88 पेज के अपने आदेश में इन बैंकों पर लगाए गए जुर्मानों को खारिज कर दिया। ट्राइब्यूनल का कहना है कि एफ.आई.यू. बैंकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने में विफल रही और वह केवल इलेक्ट्रॉनिक सबूत पर भरोसा करती है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

जीएम सरसों को लेकर अभी तक नीतिगत निर्णय नहीं

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने जीन संवर्धित (जी.एम.) सरसों फसल को वाणिज्यिक रूप से जारी करने के बारे में नीतिगत स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मुख्य न्यायधीश जे.एस.खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के वक्तव्य पर विचार किया। केन्द्र का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने कहा कि सरकार मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है और जी. एम. फसलों को वाणिज्यिक तौर पर जारी करने के मामले में उसने विभिन्न पक्षों से सुझाव और उनकी आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

सप्ताह का समय दिया

पीठ ने सरकार को जी.एम.फसलों के बारे में सुविचारित और नकनीयती के साथ लिए गए निर्णय से उसे अवगत कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 17 अक्तूबर को जी.एम. सरसों फसल का वाणिज्यिक इस्तेमाल शुरू करने के मामले में दिए गए स्थगन को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। शीर्ष अदालत ने केन्द्र से जी.एम. सरसों बीज को खेतों में उगाहने के लिए जारी करने से पहले उसके बारे में सार्वजिनक रूप से लोगों के विचार जानने को कहा।

याचिका की थी दायर

सरसों देश की सर्दियों में पैदा होने वाली एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है जो कि मध्य अक्तूबर और नवंबर में बोई जाती है। मामले में याचिकाकर्ता अरुणा रोड्रिग्स के लिए पेश होते हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार बीज की विभिन्न क्षेत्रों में बुवाई कर रही है और इसके जैव-सुरक्षा संबंधी उपायों को वेबसाइट पर डालना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। भूषण ने कहा कि इन बीजों का उचित परीक्षण किए बिना ही विभिन्न स्थानों पर इन बीजों का सीधे खेतों में परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने इस पर 10 साल की रोक लगाने की अपील की है। भूषण ने कहा कि इस संबंध में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टी.ई.सी.) की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पूरी नियामकीय प्रणाली में गड़बड़ी है इसलिए मामले में दस साल की रोक लगाई जानी चाहिए। राड्रिग्स ने जी.एम. सरसों फसल के वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल शुरू करने और इन बीजों का खुले खेतों में परीक्षण किए जाने पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की।

अरुणाचल बॉर्डर पर चीनी सेना ने की 11 घंटे की लाइव ड्रिल

बीजिंग,(आरएनएस)। चीन की सेना ने तिब्बत में गोली चलाने का 11 घंटे तक लाइव अभ्यास किया है। इस दौरान चीनी सेना ने दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया। चीन की ये चाल उस वक्त सामने आई है जब सिक्किम सेक्टर के डोकालाम क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है। सैन्य अभ्यास के समय की जानकारी दिये बगैर शुक्रवार को चीन के सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी ने अपनी खबर में कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने दक्षिण-पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में गोली चलाने का अभ्यास किया। ग्लोबल टाइम्स में आज प्रकाशित खबर के अनुसार, इस अभ्यास में पीएलए के तिब्बत मिलिट्री कमान की एक ब्रिग्रेड ने और चीन की पठारी-पहाड़ी ब्रिग्रेड ने हिस्सा लिया। पीएलए का तिब्बत कमान भारत-चीन सीमा पर नियंत्रण रेखा में तिब्बत क्षेत्र सहित कई खंडों की सुरक्षा करता है। बता दें कि इससे पहले भी चीनी सेना ने हाल ही में 5,100 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। पहली बार पीएलए की आर्मर्ड ब्रिग्रेड ने तनाव भरे माहौल में एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। इसमें चीन का सबसे एडवांस्ड युद्ध टैंक टाइप-96बी भी नजर आया था। इसके अलावा, तिब्बत की मोबाइल कम्युनिकेशन एजेंसी ने भी 10 जुलाई को ल्हासा (तिब्बत की राजधानी) में एक ड्रिल की थी। जिसमें एजेंसी के मेंबर्स ने इमरजेंसी में कम्युनिकेशन सिक्योर करने के मकसद से एक अस्थायी मोबाइल नेटवर्क खड़ा करने का अभ्यास किया था।

ड्रैगन की चाल

सिक्किम के डोकालाम क्षेत्र मे भारतीय एवं चीनी सेना के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है।

एक देशी कट्टा के साथ पांच माओवादी गिरफ्तार

औरंगाबाद,(आरएनएस)। बिहार के औरंगाबाद जिला के देव थानांतर्गत भंडारी गांव में स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पांच सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद अनुमंडल पुलिस अधिकारी पी एन साहू ने बताया कि गिरफ्तार माओवादियों में अरूणजय यादव उर्फ मृत्यंजय यादव, हरिहर यादव, प्रदीप विकर्मा, नंदू यादव और सुदामा यादव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अरूणजय यादव पडोसी राज्य झारखंड के पलामु जिला के हरिहरगंज थाना अंतर्गत लंगुराही गांव के निवासी हैं। साहू ने बताया कि हरिहर यादव और प्रदीप विकर्मा पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत सांड गांव के निवासी हैं।उन्होंने बताया कि नंदू यादव और सुदामा यादव औरंगाबाद जिला के ढिबरा थाना अंतर्गत मुरारपुर गांव के निवासी हैं। साहू ने बताया कि इन नक्सलियों के पास से एक देशी कट्टा, दो कारतूस, एक मोटर साइकिल, 20 हजार रूपये नकद राशि, 5 मोबाइल फोन तथा भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद की गयी है। उन्होंने बताया कि भंडारी गांव में इकठ्ठा हुए इन माओवादियों की मोबाइल फोन टावर को ध्वस्त करने की योजना थी।

गांवों तक तो बिजली पहुंची, घरों तक नहीं

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान से लाभान्वित होने वाले अनेक गांवों के काफी घरों में अब भी अंधेरा है और उन्हें इसका फायदा नहीं हुआ है। नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि कई गांवों का हालांकि विद्युतीकरण हो चुका है, पर इनमें काफी परिवार अभी भी बिजली से वंचित हैं और उनके लिए स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लालकिला से अपने संबोधन में कहा था कि अगले एक हजार दिन में बिजली सुविधाओं से वंचित 18,452 गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए एक मई, 2018 की समय-सीमा तय की गई है। बिजली मत्रां पांयूष गायल ने मइ म कहा था कि इन 18,452 गांवों में से 13,516 में बिजली पहुंचा दी गई है। 944 गांवों में आबादी नहीं है जबकि शेष 3,992 गांवों का एक मई, 2018 तक विद्युतीकरण किया जाएगा। 30.4 करोड़ भारतीय अभी भी बिजली सुविधा से वंचित नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एन.ई.पी.) के मसौदे में कहा है कि 30.4 करोड़ भारतीय अभी भी बिजली सुविधा से वंचित हैं। अभी 50 करोड़ लोग खाना पकाने के लिए जैव ईंधन पर निर्भर हैं। देश को अभी ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए काफी इंतजार करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययनों से यह सामने आया है कि पूर्व में कनैक्शन देने की योजनाओं और अब दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के बावजूद स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आया है। बिजली पहुंच की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है।

आयोग ने बिजली मंत्रालय को लिया आड़े हाथों

बिजली मंत्रालय को आड़े हाथों लेते हुए आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया में प्रमुख चुनौती यह है कि सिर्फ गांवों को लक्षित किया जा रहा है, घरों या परिवारों को नहीं। कई ऐसे राज्य हैं जहां विद्युतीकरण की दर ऊंची है लेकिन परिवारों को बिजली नहीं मिल पा रही है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सीधे अपने अध्यक्ष प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। सरकार के नीति निर्धारण में उसके विचारों को शामिल किया जाता है। इस बीच नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे पर टिप्पणी देने की तारीख बढ़ाकर 24 जुलाई, 2017 कर दी है।

जनधन खातों के सरकारी आकंडे जारी

नइ दिल्ली,(आरएनएस)। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जन धन खातों में जमा राशि 64,564 करोड़ रुपए की नयी उंचाई पर पहुंच गई है और इसमें से 300 करोड़ रुपए तो नोटबंदी के पहले सात महीने में ही जमा किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में एक समझी जाने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाना है।इस योजना के तहत शून्य शेष सुविधा वाले खाते खोले जाते हैं। 14 जून, 2017 तक 28.9 करोड़ जनधन खाते थे। इनमें से 23.27 करोड़ खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जबकि 4.7 करोड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और 92.7 लाख निजी बैंकों में हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन खातों में कुल 64,564 करोड़ रुपये जमा है। उनमें 50,800 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जनधन खातों में हैं जबकि 11,683.42 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 2,080.62 करोड़ रुपए निजी बैंकों में हैं। सोलह नवंबर, 2016 तक इस योजना के तहत 25.58 करोड करोड़ खाते खुलवाए गए थे जिनमें 64,252.15 करोड़ रुपए थे। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी थी। यानी सोलह नवंबर, 2016 से लेकर 14 जून, 2017 के बीच करीब 311.93 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल आठ नवंबर को 500 और 1000 रूपये के मौजूदा नोटों का चलन बंद करने की घोषणा की थी।

शशिकला की पोल खोलने वाली डीआईजी का हुआ ट्रांसफर

बेंगलुरु,(आरएनएस)। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को डीआईजी रूपा डी मुद्गल का तबादला कर दिया है। ये वही पुलिस अफसर हैं जिन्होंने जेल के आला अधिकारियों पर शशिकला से घूस लेने का आरोप लगाया था। इनका कहना था कि शशिकला ने वीआईपी ट्रीटमेंट पाने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अफसरों को 2 करोड़ रुपयों की घूस दी। रूपा का तबादला अब इंस्पेक्टर जेनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर फॉर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी के रूप में किया गया है। मुदगिल ने अपनी विवादित रिपोर्ट में लिखा कि उनके सुनने में आया है कि जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को शशिकला ने 2 करोड़ रुपये की घूस दी है जिससे उन्हें जेल के अंदर सुख-सुविधाएं मिल सकें।

इसमें डायरेक्टर सेंट्रल ऑफ प्रिजन एच एन सत्यनारायण राव का भी नाम था। इसके तहत शशिकला को अपना एक किचन भी मिला। राव का भी तबादला कर दिया गया है लेकिन उनपर किसी तरह के आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं। वो इस महीने के अंत में ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

ऐसा कहा जा रहा है कि ये तबादले इस लिए किए गए हैं जिससे निष्पक्ष जांच हो सके।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच कमिटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आई ए एस अफसर विनय कुमार करेंगे।

सिर्फ 36 फीसदी अमेरिकियों को ट्रंप का कामकाज पसंद

वाशिंगटन,(आरएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में रिकार्ड गिरावट आई है। वाशिंगटन पोस्ट और एबीसी न्यूज के हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 36 फीसदी अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज को पसंद किया है। वहीं कामकाज नापसंद करने वालों की संख्या बढ़कर 56 फीसदी हो चुकी है। 48 प्रतिशत लोगों को तो कामकाज बेहद नापसंद आया है।

जूनियर ट्रंप की रूसी वकील से मुलाकात से नाखुश लोग - राष्ट्रपति के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जेड कुश्नर ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक रूसी वकील से मुलाकात की थी। कहा गया था कि वकील से मुलाकात का मकसद विपक्षी उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के चुनाव प्रचार अभियान को नुकसान पहुंचाना था। इस मुलाकात से भी अमेरिकी नाराज हैं। सिर्फ 26 प्रतिशत लोगों ने इस मुलाकात को सही ठहराया है। जबकि 63 फीसदी ने इसे सही नहीं माना है।

अमेरिकी मानते हैं, रूस ने चुनाव को प्रभावित किया - 60 फीसदी लोगों का कहना है कि वे मानते हैं कि रूस ने राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया। वहीं 41 फीसदी के मुताबिक रूस ने ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। 44 फीसदी अमेरिकियों की राय में ट्रंप को इससे लाभ पहुंचा। सिर्फ 31 फीसदी कहते हैं कि रूस ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। 14 फीसदी की राय में ट्रंप को इससे कोई फायदा नहीं हुआ।

इन मुद्दों से नाराज हैं लोग

ओबामा केयर को हटाना, विश्व राजनीति में अमेरिका का कमजोर होना, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग करना।

ट्वीट कर ट्रंप ने खुद का बचाव किया

अमेरिका में सोमवार को यह रिपोर्ट जारी हुई। इसके बाद ट्रंप ने ट्वीट कर अपना बचाव किया है। ट्रंप ने लिखा, चुनाव के दौरान भी उन्हें ऐसे पोल कम लोकप्रिय बता रहे थे, लेकिन वे हमेशा गलत साबित हुए। हालांकि पोल जारी करने वाली एजेंसियों का कहना है कि उनके पोल सटीक रहे।

भारत के हाथ लगा लाखों टन कीमती धातुओं और खनिजों का खजाना

कोलकाता,(आरएनएस)। जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को भारतीय समुद्र से लाखों टन कीमती धातु और खनिज प्राप्त हुए हैं। 2014 सबसे पहले इनका पता चला था मंगलुरु, चेन्नई और मन्नार से। वैज्ञानिकों को जो लाइम मड, फॉस्फेट रिच और कैलकेरियस सेडीमेंट्स, हाइड्रोकार्बस, मेटेलीफेरस डिपॉजिट्स और माइक्रोनोडयूल्स मिले उनसे यह साफ पता चलता है कि समुद्र की और गहराई में जाने पर और ज्यादा मात्र में खनिज और धातु मिलने की संभावना है। तीन साल के अन्वेषण के बाद जीएसआई को 181,025 वर्ग किलोमीटर के हाई रिजोल्यूशन सीबेड मोर्फोलोजिकल डाटा, मिला है जो भारत के इकॉनोमिक जों में 10,000 मिलियन टन के लाइम मड क हान का पता चला है। इसी के साथ करवर, मंगलुरु और चेन्नई के तट पर फॉस्फेट सेडीमेंट का भी पता चला है। तमिलनाडु के मन्नार बेसिन पर भी गैस हाइड्रेट मिला है। इसके साथ ही अंडमान से फेरो मैंगनीज क्रस्ट मिले हैं और लक्ष्यद्वीप से माइक्रो-मैंगनीज नोड्यूल्स मिले हैं। इस काम को पूरा करने में तीन रिसर्च वेसेल की मदद ली गई जिसमें समुद्र रत्नाकर, समुद्र कौस्तुभ और समुद्र सऊदीकामा शामिल है। इसका मूल उद्देश्य समुद्री खनिज संसाधनों का पता लगाना था।